ट्रंप के टैरिफ हमले से बचाएंगे कम ड्यूटी वाले या ड्यूटी फ्री देश

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। अमेरिका द्वारा थोपे गए 50 से 60 फीसदी तक भारी भरकम टैरिफ से निपटने के लिए भारतीय निर्यातक अलग-अलग रास्ते तलाश रहे हैं। इनमें से एक रास्ता 'एफटीए रूट' है। इस चुनौती का सामना करने के लिए उद्यमी और निर्यातक ऐसे ट्रांजिट देशों का सहारा ले रहे हैं, जहां से उत्पादों पर अमेरिकी सीमा शुल्क या टैक्स में छूट मिलती है। ऐसा करने से वे वास्तविक मूल पते को बदल कर अमेरिकी कस्टम्स में कम टैक्स श्रेणी में प्रवेश कर सकते हैं। करीब 57 फीसदी निर्यातक ऐसे रीरूट विकल्पों पर विचार कर रहे हैं ।

हालांकि इसका लाभ अभी बड़े निर्यातकों को मिलेगा लेकिन छोटे उद्यमी अपने कंसाइनमेंट को उनके साथ जोड़ने की जुगत भिड़ा रहे हैं। टैरिफ का असर यूपी में चर्म उत्पाद, फुटवियर, हस्तशिल्प, ब्रास उत्पाद, कालीन, वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, कांच के उत्पादों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। निर्यातकों को उम्मीद है कि संकट का हल निकलेगा लेकिन चिंता इस बात की है कि जबतक समाधान नहीं निकलता, उनके अमेरिकी बाजार पर चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम या अन्य देश कब्जा कर सकते हैं।

चीन इस रणनीति का पुराना खिलाड़ी

- हस्तशिल्प से जुड़े एक बड़े निर्यातक ने कहा कि उत्पादों पर प्रतिबंध या भारी टैरिफ से बचकर उस देश में अपने उत्पाद किसी अन्य देश के रूट से भेजने की रणनीति का चीन माहिर खिलाड़ी है। उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार प्रतिस्पर्धा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं हैं क्योंकि भारतीय उत्पाद अमेरिका में प्रतिबंधित नहीं हैं बल्कि भारी टैरिफ के बोझ से दबे हैं।
- अमेरिका में उत्पाद भेजने के लिए दुबई सबसे करीबी और आसान रास्ता है। वहां एक कंपनी खोलनी होगी या किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेनी होगी, फिर उस पते से अमेरिका में उत्पाद भेजे जा सकेंगे। यूके के रूट से भी ऐसा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि छह महीने भी टैरिफ संकट रहा तो हम कम से कम 3000 करोड़ के बाजार से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे। इसी तरह फुटवियर के एक बड़े निर्यातक ने बताया कि उनकी कंपनी का विस्तार कई देशों में है। लिहाजा अब यूपी में बना माल पहले वहां डिलीवर होगा फिर अमेरिका जाएगा।

इन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता

भारत ने दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के साथ व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) शामिल हैं, जिसमें आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। हाल में यूके के साथ भी व्यापार समझौता किया गया है।

क्या होता है मुक्त व्यापार समझौता : मुक्त व्यापार समझौता ऐसी व्यवस्था है, जिसमें दो या दो से अधिक देश टैरिफ, कोटा और अन्य व्यापार बाधाओं को कम कर या खत्मकर अपने बाजार एक-दूसरे के लिए खोलते हैं। इससे उनके बीच वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन आसान हो जाता है।